हथकरघा पर घटेगा जीएसटी भार

जम्मू-कश्मीर को मिलेगा नया बढ़ावा

हस्तशिल्प पर जीएसटी घटाने की सिफारिश

श्रीनगर, 6 जुलाई.केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को जम्मू-कश्मीर के लिए उम्मीदों का नया सवेरा जगाया. श्रीनगर में एफटीआईआई- ट्रेडर्स कॉन्क्लेव - 2025 को संबोधित करते हुए, गोयल ने घोषणा की कि वह हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने की सिफारिश करेंगे.

यह कदम इस क्षेत्र के कारीगरों और उत्पादकों को बड़ी राहत देगा, जिससे उनके उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नई पहचान मिलेगी.

मंत्री गोयल ने बताया कि विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने उनसे जीएसटी के मुद्दे पर बात की थी. उन्होंने कहा, मैंने उन्हें वित्त मंत्रालय और मुझे भी एक औपचारिक आवेदन देने का सुझाव दिया है, ताकि हम इस पर गंभीरता से विचार कर सकें. हमारा लक्ष्य इन उत्पादों पर जीएसटी को कम करना है, जिससे जम्मू-कश्मीर के हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को विशेष बढ़ावा मिलेगा. यह घोषणा उन हजारों कारीगरों के चेहरों पर मुस्कान लाएगी जो अपनी कला को जीवित रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं.

गोयल ने सिर्फ जीएसटी की बात नहीं की, बल्कि स्थानीय उत्पादों को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए एक व्यापक रणनीति का भी अनावरण किया. उन्होंने बताया कि हस्तशिल्प, बागवानी वस्तुओं और पश्मीना शॉल जैसे स्थानीय उत्पादों को बेहतर ढंग से बढ़ावा देने के लिए नई डिजाइन और तकनीकों से लैस पैकेजिंग इकाइयों की सख्त जरूरत है. इसी दिशा में, उन्होंने जम्मू-कश्मीर को जल्द ही पैकेजिंग और डिजाइन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र (सेंटर ऑफ एक्सीलेंस) मिलने का आश्वासन दिया. उन्होंने अधिकारियों को भारतीय पैकेजिंग संस्थान के सहयोग से इस परियोजना को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए उपयुक्त स्थान की पहचान करने का निर्देश दिया है.

भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का बनेगा भागीदार

केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता वैश्विक क्षेत्रों को सशक्त बना रही है, और सरकार का लक्ष्य देश को आपूर्ति श्रृंखलाओं में एक विश्वसनीय वैश्विक भागीदार बनाना है .गोयल के अनुसार, भारत में डिजाइन और इनोवेशन हो रहे हैं, लेकिन अब लक्ष्य यहां पेटेंट और उत्पादन करना भी है . यह भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाएगा .मंत्री ने देवनहल्ली में कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) एयरोस्पेस विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) का दौरा किया .

सतर्क निवेशकों के बीच बाजार सीमित

अमेरिका व्यापार तनाव से बढ़ी बेचैनी

विदेशी निवेशकों ने अपनाई सतर्कता

नयी दिल्ली, 06 जुलाई (वार्ता) भारतीय शेयर बाजार में पिछला सप्ताह निवेशकों की सतर्क चाल और मिले जुले वैश्विक संकेतों के बीच कारोबार का दायरा सीमित रहा. सप्ताह के दौरान प्रमुख शेयर सूचकांक सीमित दायरे में नीचे ऊपर होते रहे.

बाजार विश्लेषकों का कहना है कि विश्व स्तर पर भू राजनीतिक तनावों तथा अमेरिका के साथ विभिन्न देशों के व्यापार संबंधों को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है. भारतीय बाजारों में जून माह की तेजी के बाद भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के बारे में अनिश्चितता से विदेशी निवेशक सावधानी का रुख किए हुए है. जुलाई के प्रथम सप्ताह में विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से बिकवाली का दबाव भी बढ़ा है.

बाजार विश्लेषणों के अनुसार हाल के सत्रों में तेज उछाल के बाद बीते सप्ताह भारतीय शेयर बाजारों में मुनाफावसूली का दौर देखने को मिला. मिश्रित वैश्विक संकेतों और भारत के खिलाफ ट्रम्प सरकार के आयात शुल्क संबंधी फैसले की 9 जुलाई की तारीख नजदीक आ गयी है. निवेशकों को अमेरिका के निर्णय की प्रतीक्षा है जो सात जुलाई को घोषित किया जा सकता है.

विश्लेषकों के अनुसार भारतीय बाजार में शेयरों का मूल्यांकन अब भी ऊंचा है. स्पष्ट संकेतों के अभाव में विदेशी संस्थागत निवेशक सतर्क हो गए हैं लेकिन जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक बाजार को समर्थन बनाए हुए हैं. घरेलू निवेशकों के इस समर्थन से बाजार की स्थिति संभली हुई है. अमेरिका में प्रशुल्क दरों को लेकर अनिश्चितता से धातु, वाहन और वित्तीय क्षेत्र के शेयर दबाव में दिखे ,पर बड़े रक्षा खरीद सौदे के सरकार के फैसलों से उत्साहित रक्षा शेयरों ने बेहतर प्रदर्शन किया, जो रणनीतिक क्षेत्रों पर सरकार के निरंतर ध्यान को दर्शाता है. सरकार ने इसी सप्ताह 1.06 लाख करोड़ रुपये के रक्षा खरीद के प्रस्तावों को मंजूरी दी है जिसका अधिकतर ठेका घरेलू कंपनियों को जाएगा.

फार्मा सेक्टर में 11 प्रतिशत बढ़त का अनुमान : रिपोर्ट

- अस्पताल और डायग्नोस्टिक से बढ़ेगी रफ्तार
- अस्पताल खंड में 17% की मजबूती संभावित
- डायग्नोस्टिक क्षेत्र में 14% सालाना वृद्धि का अनुमान

नई दिल्ली, 6 जुलाई.कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज की एक रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026 की पहली तिमाही में फार्मास्युटिकल कंपनियों की बिक्री और ईबीआई टीडीए में साल-दर-साल 11 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है.

यह वृद्धि अधिकांश बाजारों में निरंतर गति से प्रेरित होगी, हालांकि अप्रैल और मार्च में घरेलू मांग में सुस्ती से लाभ थोड़ा प्रभावित हो सकता है. रिपोर्ट में बताया गया है कि अस्पताल खंड में बिक्री और ईबीआईटीडीए दोनों में 17 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि होने का अनुमान है.

यह वृद्धि मरीजों की बढ़ती संख्या, नए बिस्तरों के जुड़ने और प्रति अधिग्रहित बिस्तर औसत राजस्व में मामूली वृद्धि से समर्थित होगी. डायग्नोस्टिक्स क्षेत्र में, वॉल्यूम वृद्धि, बेहतर उत्पाद मिश्रण और विलय एवं अधिग्रहण गतिविधियों के कारण बिक्री में 14 प्रतिशत की साल-दर-साल वृद्धि होने की उम्मीद है.

भारत का फार्मास्युटिकल बाजार वित्त वर्ष 2023-24 में 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था, जिसमें घरेलू खपत 23.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर और निर्यात 26.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था. भारतीय घरेलू फार्मा उद्योग मात्रा के हिसाब से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और उत्पादन मूल्य के हिसाब से 14वां सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है. जेनेरिक दवाओं, बल्क ड्रग्स, ओवर-द-काउंटर दवाओं, टीकों, बायोसिमिलर और बायोलॉजिक्स सहित एक अत्यंत विविध उत्पाद आधार के साथ, भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग की वैश्विक स्तर पर मजबूत उपस्थिति है.

विकसित भारत के लिए 10% वृद्धि जरूरी

नयी दिल्ली, 06 जुलाई.भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के अध्यक्ष राजीव मेमानी ने कहा है कि सरकार के 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए देश को सालाना औसतन 10 प्रतिशत की मूल्यानुसार (नॉमिनल) सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर हासिल करनी होगी. मूल्यानुसार जीडीपी किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है, जिसे वर्तमान बाजार मूल्यों पर मापा जाता है, बिना मुद्रास्फीति के समायोजन के.

मेमानी ने बताया, भारत को विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए औसतन लगभग 10 प्रतिशत की मूल्यानुसार वृद्धि की आवश्यकता होगी.सीआईआई के नवनियुक्त अध्यक्ष ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौता, जिसे जल्द ही अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है, %अनिश्चितता% के बादल को दूर करेगा. यह समझौता भारतीय कंपनियों, विशेषकर श्रम-प्रधान क्षेत्रों में, को बड़े बाजार तक पहुंच प्रदान करेगा. उन्होंने जोर दिया कि यह व्यापार समझौता प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अधिक संयुक्त उद्यमों और साझेदारियों का भी मार्ग प्रशस्त करेगा, जिससे भविष्य के लिए स्पष्ट दिशा मिलेगी और इसका बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा.

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की उम्मीद

श्रम-प्रधान उद्योगों को मिल सकता है लाभ

सीआईआई के अनुसार, मजबूत घरेलू मांग के कारण चालू वित्त वर्ष (2025-26) के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था के 6.4-6.7 प्रतिशत की दर से बढ़ने की उम्मीद है. हालांकि, भू-राजनीतिक अनिश्चितता के कारण नकारात्मक जोखिम बना हुआ है. मेमानी ने भारत की आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छी और बहुत स्थिर बताया.

सोने-चांदी की चमक फिर बढ़ी

नई दिल्ली, 6 जुलाई. सोने और चांदी दोनों की कीमत में इस हफ्ते बढ़त देखी गई है. सोने के दाम में 1,200 रुपए से अधिक का इजाफा हुआ. वहीं, चांदी का भाव 2,300 रुपए से अधिक बढ़ गया है.इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत 97,021 रुपए है, जबकि एक हफ्ते पहले इसी दिन यह 95,784 रुपए थी, जो कि सोने की कीमत में 1,237 रुपए की बढ़त को दर्शाता है. 22 कैरेट सोने का दाम बढ़कर 88,871 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जो कि पहले 87,738 रुपए था. वहीं, 18 कैरेट सोने की कीमत 71,838 रुपए प्रति 10 ग्राम से बढ़कर 72,766 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई है.वहीं, समीक्षा अवधि में चांदी की कीमत 2,387 रुपए बढ़कर 1,07,580 रुपए प्रति किलो हो गई है.

डॉलर के मुकाबले रुपया स्थिर

अमेरिका में रोजगार आंकड़ों से डॉलर को बल

नयी दिल्ली, 06 जुलाई (वार्ता) अमेरिका के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते को लेकर अनिश्चितता तथा शेयर बाजारों में विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली के दबाव के बावजूद जुलाई माह के पहले सप्ताह में विदेशी विनियम बाजार में भारतीय रुपये में कुल मिलाकर स्थिरता दिखी.

अमेरिका के साथ अच्छे व्यापार समझौते की बाजार की उम्मीद पूरी हुई तो इस सप्ताह रुपये को काफी सहारा मिल सकता है.सप्ताह के दौरान जारी अमेरिका के गैर कृषि क्षेत्र के रोजगार आंकड़े बाजार की उम्मीद से बेहतर रहे. इससे वहां ब्याज दर में स्थिरता की संभावना के बीच डालर के मुकाबले रुपया सप्ताह के मध्य में मजबूत रहा . लेकिन सप्ताह के अंत में थोड़ी गिरावट के चलते करीब करीब यह पिछले सप्ताह के स्तर पर स्थिर रहा. जुलाई के पहले सप्ताह में बाजार में कारोबार सीमित दायरे में रहा.

पहली जुलाई को रुपया 85.70 के आसपास खुलने के बाद मजबूत हो कर 85.59 रुपये प्रति डालर के दायरे में बदं हुआ था. गुरुवार को स्थानीय मुद्रा मजबूत होकर 85.31 प्रति डालर पर बंद हुयी.

सरकारी बैंकों में 50 हजार नौकरियां

चालू वित्त वर्ष में होंगे 50,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती

एसबीआई अकेले 20,000 कर्मचारियों की करेगा नियुक्ति

नयी दिल्ली, 06 जुलाई. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अपनी बढ़ती कारोबारी जरूरतों और विस्तार के लिए चालू वित्त वर्ष में करीब 50,000 कर्मचारियों की भर्ती करेंगे.

विभिन्न बैंकों से जुटाए गए आंकड़ों के अनुसार, कुल नई भर्तियों में से करीब 21,000 अधिकारी होंगे और बाकी लिपिक सहित अन्य कर्मचारी होंगे.सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंकों में से सबसे बड़ा ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) इस वित्त वर्ष में विशेषज्ञ अधिकारियों सहित करीब 20,000 लोगों की नियुक्त करने जा रहा है. इस प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए, एसबीआई ने देशभर में अपनी शाखाओं में ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए पहले ही 505 प्रोबेशनरी ऑफिसर और 13,455 जूनियर एसोसिएट्स की भर्ती कर ली है.

तेलंगाना में 10 घंटे के कार्यदिवस को मंजूरी

हैदराबाद, 6 जुलाई. तेलंगाना सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों को प्रतिदिन 10 घंटे तक काम करने की अनुमति दी है. यह नीति श्रमिक सुरक्षा उपायों के अधीन है, जिसमें प्रति सप्ताह अधिकतम 48 घंटे कार्य और अतिरिक्त घंटों के लिए ओवरटाइम भुगतान शामिल है. छह घंटे से अधिक काम पर 30 मिनट का ब्रेक अनिवार्य होगा, और ओवरटाइम सहित कुल कार्य अवधि 12 घंटे से अधिक नहीं होगी, साथ ही प्रति तिमाही अधिकतम 144 घंटे ओवरटाइम की सीमा तय की गई है.

भारत की विकास दर बनी वैश्विक सिरमौर

निर्यात और शेयर बाजार ने रचा नया इतिहास

नई दिल्ली, 6 जुलाई.भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर वित्त वर्ष 2024-25 में 6.5 प्रतिशत रही है, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक है. साथ ही, इस दौरान देश का निर्यात भी सार्वकालिक उच्चतम स्तर 824.9 बिलियन डॉलर पर रहा है.यह आंकड़े दिखाते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था आत्मविश्वास के साथ लगातार बढ़ रही है.

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में देश की विकास दर इसी आंकड़े के आसपास रहने की उम्मीद है.संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, भारत की विकास दर इस साल 6.3 प्रतिशत और अगले साल 6.4 प्रतिशत की दर से बढ़ सकती है, जबकि भारतीय उद्योग परिसंघ का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में देश की विकास दर 6.40 से 6.70 प्रतिशत के बीच रह सकती है.अर्थव्यवस्था के अच्छे प्रदर्शन के कारण देश के निर्यात में भी तेजी से इजाफा हो रहा है. भारत का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में 824.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जो वित्त वर्ष 2023-24 में 778.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 6.01 प्रतिशत अधिक है.

समाचार विशेष

शिवसेना यूबीटी फेक नैरेटिव बनाने वाली फैक्ट्री

फडणवीस ने यूबीटी और ठाकरे बंधुओं के छुपे एजेंडे का किया पर्दाफाश

मुंबई. रवींद्र चव्हाण को पार्टी के नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित किए जाने के मौके पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चव्हाण की प्रशंसा के बाद महाराष्ट्र में जारी हिंदी बनाम मराठी विवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे पर निशाना साधा.

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में केवल एक ही भाषा अनिवार्य है, वह है मराठी. उन्होंने कहा कि इस वजह से सभी को मराठी सीखनी ही चाहिए. लेकिन इसके साथ-साथ हमें हिंदी पर भी गर्व है. हमें भारत की हर भाषा पर गर्व है. उन्होंने आदित्य ठाकरे और अमित ठाकरे का नाम लिए बगैर कटाक्ष करते हुए कहा कि अपने बच्चों को बॉम्बे स्कॉटिश में पढ़ाना और अंग्रेजी बोलना, ऐसे विदेशी भाषा अंग्रेजी के लिए लाल गलीचे बिछाना और भारतीय भाषाओं का विरोध हमें बिलकुल भी बर्दाश्त नहीं है. हमने एक समिति बनाई है और हम किसी के दबाव में आए बिना छात्रों के हित में निर्णय लेंगे.

हिंदी अनिवार्य का दुष्प्रचार-सीएम- मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि देश में त्रिभाषा फार्मूला लागू होने के बाद, उद्धव की सरकार ने उस फार्मूले को कैसे स्वीकार किया जाए, यह तय करने के लिए एक समिति बनाई थी. उस समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि कक्षा 1 से 12 तक हिंदी को अनिवार्य किया जाना चाहिए. उस रिपोर्ट को उद्धव की कैबिनेट ने स्वीकार किया. उन्होंने उस पर हस्ताक्षर किए. हमारी सरकार ने तय किया कि हिंदी या कोई अन्य भाषा तीसरी भाषा के रूप में सीखनी चाहिए. लेकिन इन्होंने सिर्फ हिंदी अनिवार्य का दुष्प्रचार शुरू कर दिया.

फडणवीस ने उद्धव की पार्टी शिवसेना यूबीटी को फेक नैरेटिव बनाने वाली फैक्ट्री करार देते हुए कहा कि लोकसभा में फेक नैरेटिव के जरिए इन्होंने चुनाव परिणाम प्रभावित किया था लेकिन विधानसभा चुनाव में हार के बाद भी इनकी फेक नैरेटिव की फैक्ट्री बंद नहीं हुई. अब महानगरपालिका चुनाव नजदीक हैं. जिला परिषद चुनाव नजदीक हैं. तो इनका मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश का आरोप शुरू हो गया है. लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि किसी के बाप में इतना दम नहीं है कि वह मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर सके.

सिर्फ राजनीति के लिए मराठी

उद्धव का नाम लिए बगैर फडणवीस ने कहा कि ये सिर्फ मराठी के नाम पर राजनीति करते रहे हैं. चुनाव के दौरान इन्हें मराठी लोगों की याद आती है. मुंबई, गिरगांव के मराठी लोग इनकी वजह से बाहर गए. भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद, हमने मुंबई के विकास के लिए काम किया है. हमने मराठियों को बीबीडी चाल, अभ्युदय नगर में घर दिया. हम ही हैं जिन्होंने धारावी में गरीबों को घर दिए. महाराष्ट्र के हर कोने में किसान समृद्ध हों, युवाओं को काम मिले, ये हमारा प्रयास है. उन्होंने आगे कहा हमारी सरकार ने 16 लाख करोड़ रुपए के अनुबंधों पर हस्ताक्षर करके राज्य को नंबर एक पर लाया गया है. हम गरीब किसानों को पानी देना चाहते हैं. हम सूखे को अतीत की बात बनाना चाहते हैं. हमने 2014 के बाद जो कहा, वह किया है.

बीएमसी चुनाव अकेले लड़ेगी कांग्रेस

मुंबई. महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है. एक तरफ जहां ठाकरे बंधु एक होने में जुटे हैं. वहीं दूसरी ओर कांग्रेस महाविकास आघाडी (एमवीए) से अलग होने की राह तलाश रही है. विधानसभा चुनाव में गठबंधन की करारी हार के बाद तीनों पार्टियां साथ चुनाव लड़ने से कतरा रही हैं. कांग्रेस लगातार अलग चुनाव लड़ने के संकेत दे रही है.

कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला के बयान के एक दिन बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस के भीतर यह "बहुत मजबूत राय है कि पार्टी को बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) का चुनाव अकेले लड़ना चाहिए.

पृथ्वीराज चव्हाण के बयान के एक दिन पहले कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी रमेश चेन्निथला ने कहा था कि कांग्रेस आगामी 7 जुलाई को इस बारे में निर्णय करेगी कि बीएमसी का चुनाव एमवीए के सहयोगी दलों के साथ मिलकर लड़ना है या कोई दूसरी राह अपनानी है. पृथ्वीराज चव्हाण ने एक साक्षात्कार में कहा कि जिला परिषदों, पंचायत समितियों और दूसरे स्थानीय निकाय के चुनावों में आमतौर पर गठबंधन के बारे में कांग्रेस जिला इकाई निर्णय लेती रही है, लेकिन यह तय है कि सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति से संबंधित किसी भी पार्टी के साथ तालमेल नहीं होगा. क्या कांग्रेस बीएमसी चुनाव गठबंधन में लड़ेगी या अकेले? इस सवाल के जवाब में पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि इस बारे में दो राय हैं. एक यह है कि कांग्रेस का झंडा हर घर के हर बूथ पर जाना चाहिए. यदि आप बहुदलीय गठबंधन में लड़ते हैं, तो हमें कुछ निर्वाचन क्षेत्र छोड़ने होंगे.

विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को हुआ नुकसान

पृथ्वीराज चव्हाण ने कहा कि विधानसभा चुनाव में हमारा अनुभव बहुत खराब था. हमारे कुछ गठबंधन सहयोगियों ने उन सीटों पर लड़ने पर जोर दिया, जहां उनका कोई आधार नहीं था और उन्हें वे टिकट दिए गए तथा उन्हें केवल 2,000 वोट मिले. इसलिए निश्चित रूप से हमें नुकसान हुआ. बता दें कि एमवीए में कांग्रेस के अलावा शिवसेना (यूबीटी) और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) शामिल है.

पंजाब छोड़ गुजरात पहुंचे केजरीवाल

विसावदर सीट उपचुनाव में मिली जीत ने नई जान फूंकी

अहमदाबाद. आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने गुजरात को छोड़ा हुआ था. उनका सारा ध्यान दिल्ली और पंजाब पर था. दिल्ली विधानसभा का चुनाव हारने के बाद उन्होंने पंजाब पर और फोकस किया था.

इसके अलावा हरियाणा से कुछ उम्मीद जोड़ी थी. लेकिन गुजरात की विसावदर सीट के उपचुनाव में मिली जीत ने उनमें नई जान फूंक दी है. वैसे यह सीट आप की ही थी. 2022 के विधानसभा चुनाव में भूपेंद्र भयानी आप की टिकट से जीते थे लेकिन पिछले दिनों वे पाला बदल कर भाजपा में चले गए. सीट उनके इस्तीफे से खाली हुई तो उपचुनाव में केजरीवाल ने अपने सर्वाधिक भरोसे के नेता गोपाल इटालिया को टिकट दिया. ध्यान रहे भाजपा यह सीट 2007 से नहीं जीती है. यह सीट भाजपा के दिग्गज नेता केशुभाई पटेल की रही है और लेउवा पटेल बहुतायत वाली इस सीट पर कहा जाता है कि केशुभाई का भूत भाजपा को नहीं जीतने देगा. गौरतलब है कि केशुभाई को हटा कर ही 2001 में नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री बनाया गया था.

विशेष | **पैठ बनाने की आगे आयी पार्टी**

पसमांदा मुसलमानों पर भाजपा की नजर

पटना. भाजपा ने वक्फ कानून को पसमांदा मुसलमानों के हित में बता रही है. पार्टी ने आबादी और वोट बैंक से मजबूत मान जाने वाले पसमांदा मुसलमानों से कहा कि विपक्ष के लोग उन लोगों को बरगला रहे हैं. जबकि अल्पसंख्यकों का सच्चा हितैशी भाजपा और एनडीए ही है.

इसी कड़ी में भाजपा के प्रदेश कार्यालय में पसमांदा मिलन समारोह का आयोजन किया गया. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ दिलीप जायसवाल और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इस कार्यक्रम में शामिल हुए. राज्य के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में पहुंचे पसमांदा समाज के लोगों को भाजपा नेताओं ने विकास का भरोसा दिलाया. इस दौरान बड़ी संख्या में पसमांदा समाज के लोगों ने भाजपा की सदस्यता भी ली. उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने पसमांदा मुसलमानों के बेहतरी के लिए कई कार्य किये हैं.

नीतीश सरकार ने दिया आरक्षण

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि जब अटल बिहारी बाजपेयी सरकार ने महिला आरक्षण बिल लाया था, तब राजद के सदस्यों ने सदन में बिल की कॉपी फाड़ कर अपना महिला -विरोधी चेहरा दिखाया था. बाद में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने महिला आरक्षण बिल को पारित कराया. श्री चौधरी ने कहा कि अब लालू प्रसाद के लोग उस नए वक्फ कानून के विरुद्ध भ्रम फैला कर वोट बैंक की राजनीति करने में लगे हैं, जो गरीब मुसलमानों के पक्ष में है. लालू परिवार पर हमलावर सम्राट चौधरी ने कहा, बिहार में लालू प्रसाद का परिवार अपराधीकरण और गुंडागर्दी के लिए जिम्मेदार है. उनके 15 साल के राज में अपराध को सत्ता का संरक्षण मिलने से व्यापारियों-उद्यमियों का सामूहिक पलायन हुआ.